ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Media Bite **06 December, 2020**

Shri Pawan Khera, Spokesperson, AICC addressed media at AICC Hdqrs, today.

श्री पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व देख रहा है भारत के किसानों को दिल्ली के बाहर सड़क पर इस सर्दी में बैठे हुए। दिन-रात लाखों किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि कब देश की निष्ठुर सरकार का मन पसीजेगा।

बुनियादी सवाल क्या है – बुनियादी सवाल यह है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई? आखिर क्या वजह है कि आनन-फानन में जून में अध्यादेश लाए जाते हैं। जब देश का ध्यान कोविड़ पर केन्द्रीत हो, तब देश की सरकार चुप-चाप अपने चंद उद्योगपति मित्रों की सेवा में हाजिर दिखाई देती है। ये प्रश्न बहुत वाजिब है, ये प्रश्न, ये सवाल हम सबके दिमाग में है। आखिर क्यों जल्दबाजी में संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए इन तीनों बिलों को पारित किया जाता है, विपक्ष को निलंबित कर दिया जाता है, ताकि कोई अपोजिशन दिखे ही नहीं और चुपचाप से बिल पास हो जाए और कानून बन जाएं? आखिर क्या कारण है कि जिन किसानों के तथाकथित लाभ के लिए आप सामने ये दिखाते हो पूरे विश्व को कि इनका लाभ होने वाला है और ऐसे कानून पारित कर जाते हो, उन कानून को बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं किसानों की सलाह नहीं ली जाती है? तो ये स्थिति इन कारणों से बनी है, इस स्थिति का ये छोटा सा इतिहास है, जो आप सबने देखा इस जून से लेकर और अब तक।

आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, उसके पीछे सरकार का एक षड़यंत्रकारी रवैया रहा है। जिसके चलते क्रोधित किसान दुखी मन से अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। एक तो आपने किसान को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया और वहीं दूसरी और आपके मंत्री, आपके राज्यों के मंत्री गैरजिम्मेदाराना बयान देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कुछ मंत्री हमारे किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट करार देते हैं और पड़ोस के हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें खालिस्तानी करार देते हैं। माफ कीजिएगा चाटूकार मीडिया में तो प्लांट भी कराया जाता है कि ईडी की जांच होगी किसानों की फॉरेन फंडिग हो रही है। मजाक बना रखा है आपने। देश के किसान हैं, 62 करोड़ किसान हैं इस देश में, लाखों किसान बाहर दरवाजे पर खड़े हैं दिल्ली के और इस तरह की बात कर रहे हैं उनके विषय में।

इस देश के किसानों की समस्या की मुख्य वजह क्या रही है – एमएसपी। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में आप बार-बार बोलते हैं कि हमने लागू कर दी। पूछिए ना, कौन सा फॉर्मूला लागू किया? किसान उससे व्यथित हैं और अब आपने एपीएमसी और एमएसपी पर एक बहुत बड़ा संकट ले आए, जिससे किसान

क्रोधित हुए। सीधे-सीधे आपने एपीएमसी व्यवस्था पर चोट की है, जिसके चलते आपने एमएसपी पर भी चोट की है। मेरे साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने परसों बहुत स्पष्ट तौर से एमएसपी का मुद्दा समझाया था आपको। तो अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने की नीयत से ही जो जमाखोरी को प्रोत्साहन देने के लिए इन कानूनों को लागू किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो जाता है, कृषि मंत्री गलती से ही सच निकल गया उनके मुँह से। उन्होंने तो परसों एक इंट्रव्यू में बोल ही दिया कि अगर हम ये कानून वापस लेते हैं, तो उद्योगपति हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि ये कानून वापस क्यों ले रहे हैं? उन्होंने तो उद्योगपतियों के नाम भी लिए।

ये हम भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं कि लॉकडाउन में अगर एक वर्ग निरंतर काम कर रहा था, तो वो था इस देश का किसान। लॉकडाउन में भी वो खेत में था। इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर कुछ भी बचा है इस लॉकडाउन के बाद तो वो इस किसान की मेहनत का नतीजा के कारण बचा है।

एक तरफ किसानों से वार्तालाप का स्वांग रचा जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है। वहाँ वार्तालाप शुरु होने से पहले वाराणासी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कानून वापस ही नहीं लिए जाएंगे। क्या ऐसे होती हैं समझौता वार्ताएं? हमने भी कई समझौता वार्ताएं की हैं। आप पहले ही दरवाजे बंद कर दो अपने दिमाग के, राजधानी के दरवाजे बंद कर दो और फिर कहो कि हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। आपकी नीयत स्पष्ट हो जाती है कि आप नहीं चाहते कि ये वार्तालाप सफल हो। आप नहीं चाहते कि कि किसानों की बात मानी जाए। आप नहीं चाहते कि आप ये कानून वापस लें, क्योंकि आपके मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि उद्योगपति नाराज हो जाएंगे।

नोटबंदी से लेकर और कृषि के इन तीन काले कानूनों तक का सफर अगर आप मोदी जी के प्रधानमंत्रीत्व काल का देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि जो-जो निर्णय उन्होंने स्वयं लिए जिसमें पिछली सरकारों का कोई योगदान नहीं था, वो निर्णय इस देश को नागवार गुजरे हैं, इस देश को नुकसान पहुंचा कर गए हैं।

कांग्रेस पार्टी ने, विशेष तौर पर श्री राहुल गांधी ने किसानों के पक्ष में सदैव अपनी आवाज़ उठाई है। पिछले कुछ महीनों से हमारी पार्टी ने निरंतर किसान सम्मेलनों, हस्ताक्षर अभियानों व ट्रैक्टर रैलियों के माध्यम से किसानों के हक़ की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आगामी 8 दिसम्बर को होने वाले भारत बंद को कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन है। ज़िला व प्रदेश मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर हम यह सुनिश्चित करेंगे के किसानों की माँगों के समर्थन में आहूत भारत बंद पूर्णतः सफल रहे।

Shri Pawan Khera said- The entire world is witnessing the plight of our farmers. The entire world is seeing the horrible sights of farmers sitting outside the capital in the middle of night during the harsh winters, waiting for the Government to listen to them. After all, we need to ask the fundamental question, how did we reach this situation? In the middle of a Covid pandemic, the Government in June surreptitiously brings ordinances, Why ? What was the hurry, everybody wants to know, and what was the hurry? The entire country was focused on Covid and its fallout, the economic fallout, the social

fall out, the health fall out, but, the Government was busy surreptitiously bringing ordinances to help its industrialist, corporate friends. Where was the need for the hurry ? Even during the Parliament session, why were these bills enacted so fast ? You suspended the opposition parties from the Parliament, you did not follow due parliamentary procedure and hurried through the passing of the bills? Where was that need? Why was the hurry shown? After all, what are the reasons that the same farmers were not taken into consideration, their advice were not taken into consideration. Now, you are hiding behind the so called interest of the farmers? If you were really bothered about the interest of the farmers, you would have not taken their advice before forming these legislations, supposedly in their favour. So, what we are seeing today, is a result of a conspiracy between Government and its corporate friends wherein the victim would be the farmers and farmer knows this and farmer knows his or her interest much more than those of us sitting in powerful positions, whether in Government or in Parties.

On the one hand, you forced the farmers to come on the roads to fight for their rights. On the other hand, your Ministers in the States and in your Union Cabinets make such horrible & humiliating comments. It appears as you don't treat farmers as your own. You have a Minister in Haryana, who accuses the farmer of being agents of China and Pakistan, I mean ridiculous as it can be. You have a Chief Minister of Haryana who calls them Khalistani and there is a section of the Media, I am afraid who is more loyal than the king. That section of the media has been running stories that there will be ED investigation into foreign funding of these farmer protests. I mean, if it was not so tragic, it could have been laughable.

The complaint of the farmer has been MSP. That has been a bone of contention. You kept saying that you are delivering on the Swaminathan Commission report but the formula you adopted was not adhering to the Swaminathan Commission report. My Colleague Randeep Singh Surjewala Ji has elaborated on this day before yesterday so I don't need to go down that road again. Now, with the new legislations what you have done is you have attacked the very structure of the APMC, thereby attacking the MSP itself. The entire APMC regime is what supports the MSP. So in the absence of the APMC regime, where will you give the MSP? How will you give the MSP? Therefore, the demands of the farmers are absolutely valid. Their apprehensions are absolutely valid, their fears are absolutely justified. We all know, why you are so keen on these legislations, but, we should not forget specially those of us sitting in powerful positions in Government and parties that even during the lockdown when we were all sitting in our houses, well not, most of you were not, you were still working hard, if there was one section which was working day in and day out, it was the farmers, they were on their fields. It is because of them the economy still has some saving grace left.

On the one hand you were talking about your intention to talk to the farmers, to engage with them, on the other hand in Varanasi, the Prime Minister stands and says- No, the laws will not be rolled back. Is this how you do, is this how you engage with the people, who are upset with your legislations. We have engaged with a lot of such groups. This is no way you shut your minds, you shut the doors of the capital, you don't allow them in, you don't allow them to talk to you and then you expect them to listen to you, that is not possible.

The Agriculture Minister of India, I don't know how, but, he somehow couldn't control himself, if he withdraw these legislations, some corporates will get angry and they will ask us, they will question us, why are you withdrawing these legislations, so some truths, somewhere in this Government came out, something, which we have all along known, the farmers have known it. Now, it has come from the Agriculture Minister's own mouth.

From *Notebandi*, Demonetisation to these three black laws, one thing is very clear. Whenever the Prime Minister has done something on his own with no traces, no institutional wisdom from the previous Governments, the results have been disastrous.

From here, I would also like to announce that the Congress Party extends its whole hearted support to the *'Bharat Band'* on 8th December. Our leader Shri Rahul Gandhi through Tractor Rallies, Signature Campaign, Kisan Sammelans has been raising the Party's voice in support of the farmers. All our district and Pradesh units will participate in this *'band'*. They will hold demonstrations and ensure that the *band* is successful.

Thank you.

एक प्रश्न के उत्तर में श्री खेड़ा ने कहा कि यह सोचने का विषय हम सबके लिए है क्योंकि भारत की साख की जिम्मेदारी सिर्फ़ सरकार की तो नहीं है, हम सबकी है। हम सब चिंतित हैं ये देखते हुए कि पूरा विश्व इस बारे में चर्चा कर रहा है और अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इस स्थिति को बचाया जाए ताकि हमारी और जगहंसाई न हो, पूरा विश्व हमारे किसानों के बारे में जिस तरह से बात कर रहा है, इस आंदोलन के बारे में जिस तरह से बात कर रहा है, देश की छवि को भारी नुकसान हो रहा है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री खेड़ा ने कहा कि- जो कृषि राज्यमंत्री ने कहा, वो किसानों को स्वीकार्य नहीं है, वो आपने कल देख लिया। किसानों की जो मांग है, वह बार-बार रख चुके हैं सरकार के सामनें। सरकार को चाहिए कि उनकी मांग माने।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री पवन खेड़ा ने कहा कि ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसी डिबेट है, जो निरंतर होते रहनी चाहिए। इस डिबेट से परिभाषाएं उत्पन्न होती हैं। सेंट्रिज्म की परिभाषा, हम अपने आपको बड़े गर्व से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। सेकुलरिज्म की परिभाषा, ये तमाम परिभाषाएँ हर नई पीढ़ी के लिए इन्हीं डिबेट से निकल कर आती हैं। अगर हम किसी एक ऐसी पार्टी के विरुद्ध हैं, जो सिर्फ

हिंदुओं की बात करे, पूरे देश की बात ना करे, तो हम ऐसी पार्टी के भी विरुद्ध हैं, जो सिर्फ मुसलमानों की बात करे और पूरे देश की बात ना करे। क्योंकि सेंट्रिज्म, सेकुलरिज्म और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के हर वर्ग की बात करती है। वो जातियों में मतभेद नहीं रखती, वो धर्मों में भेद नहीं रखती, वो भाषाओं में भेद नहीं रखती और इस पीढ़ी के लिए भी ये परिभाषा फिर से बाहर आनी जरुरी है, सार्वजनिक होनी जरुरी है कि क्या परिभाषा होती है सैंट्रिज्म की। सैंट्रिज्म का मतलब ये नहीं है कि लैफ्ट को भी रिजेक्ट कर दो और राइट को भी रिजेक्ट कर दो। सैंट्रिज्म का मतलब ये है कि लैफ्ट और लाइट दोनों का सम्मिश्रण हो। ना एक्सट्रिम (extreme) लैफ्ट का स्थान होता है, ना एक्सट्रिम राइट का स्थान होता है, ये होता है सैंट्रिज्म। तो उनका जो बयान है, उससे इस परिभाषा पर डिबेट होना बहुत आवश्यक है।

8 तारीख को किसानों द्वारा आहूत 'भारत बंद' के संदर्भ में पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री पवन खेड़ा ने कहा कि 8 तारीख का बंद सफल होगा। कई लोग, आप उस दिन संसद में अगर पूरी प्रक्रिया फॉलो करते तो तथाकथित जो एनडीए के पार्टनर हैं, वो भी खुल कर बाहर आते। जरुरत नहीं है, सबको आना ही पड़ेगा। किसान को आप कैसे इग्नोर कर देंगे, किसान की मांगों को आप कैसे दरकिनार कर देंगे। आपको उन्हीं के पास जाना है, बार-बार जाना है।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC